



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4135]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार अक्तूबर 18, 2018/आश्विन 26, 1940

No. 4135]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18, 2018/ASVINA 26, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5326 (अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, कि बैंकिंग उद्योग में लगी हुई सेवाएं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची के मद 2 के अधीन सम्मिलित हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक उपयोगी सेवा है ;

और केन्द्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 11 अप्रैल, 2018 में अंतिमतः प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1569(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2018 उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए उक्त उद्योग 21 अप्रैल, 2018 से छह मास के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में और छह मास की अवधि के लिए उक्त उद्योग को लोक उपयोगी सेवा की स्थिति का विस्तार करना अपेक्षित है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंकिंग उद्योग में लगी हुई सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए तारीख 21 अक्तूबर, 2018 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[फा. सं. एस-11017/5/97-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th October, 2018

S.O. 5326(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the Banking industry, which is covered under item 2 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 21st April, 2018 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O.1569(E), dated the 11th April, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 11th April, 2018;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the Banking industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 21st October, 2018.

[F.No. S-11017 / 5 / 97- IR(PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.